EDITORIAL

THE TRAGEDY OF SALARY AND PENSION REVISION

The issue of salary revision for absorbed telecommunications employees in BSNL (transferred from DoT) and the pension revision for retired employees remains unresolved. Both revisions have been pending since 01.01.2017. Neither the management nor the government appears to recognize the gravity of these matters, addressing them in a dismissive manner.

On 26th November 2024, the Hon'ble Minister of Communications responded to a letter from Shri S. Venkatesan, Member of Parliament, stating that the pension revision for retired BSNL employees cannot proceed until the salary revision for working employees is completed. The Minister further clarified that the salary revision is hindered by BSNL's ongoing financial crisis and emphasized that pension revision is linked to salary revision.

Additionally, the Minister mentioned that the pension revision issue is pending before the Hon'ble Delhi High Court. However, it is widely known that the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal, New Delhi, had already ruled in favor of pensioners. The Department of Telecommunications (DoT), under instructions from the Ministry of Communications, has complicated the matter by filing an appeal. If the Delhi High Court rules in favor of pensioners, it is likely that the case will be escalated to the Hon'ble Supreme Court by the Central Government. This demonstrates the government's deliberate attempts to delay resolution rather than solve employees' problems.

In the year 2000, employees in the Department of Telecommunications opted to work for BSNL after its corporatization, based on assurances that their services would be protected and pensions paid from the government exchequer. However, the current scenario indicates that the government is reneging on its written promises made through the Union Cabinet's decisions.

BSNL, a prestigious public-sector company, played a pivotal role in delivering telecommunications services across India for decades. Today, however, BSNL employees and pensioners face a severe crisis related to salary and pension revision. This issue is not limited to financial challenges but also adversely impacts employee morale and organizational efficiency.

The last salary revision for BSNL employees occurred in 2007. Since then, financial losses, government neglect, and competition from private companies have weakened BSNL’s position. Employees state that the lack of salary revision has significantly impacted their standard of living.

Pensioners are struggling with the erosion of their pensions due to inflation.

Despite announcing several financial packages to revive BSNL, the government has not prioritized salary and pension reforms, reflecting its indifference toward employee welfare.

The absence of fair salaries makes employees feel insecure, negatively affecting their performance.

To compete with private companies like Jio and Airtel, BSNL requires skilled human resources. Without fair wages and benefits, talented employees are leaving the organization.

For pensioners, the lack of pension revision amidst rising inflation poses severe hardships.

The government must expedite the salary revision process to restore employee confidence.

Implement policies for regular pension adjustments in line with inflation.

BSNL must invest in new technologies and services to enhance revenue and competitiveness.

The government should devise long-term strategies to enable BSNL to compete effectively with private companies.

The issue of salary and pension revision for BSNL employees demands urgent attention, not only for financial improvement but also to rebuild trust between the government and employees. Delays in addressing this crisis will adversely affect employees’ lives and jeopardize the future of this significant public-sector enterprise. The time has come for the government to reevaluate its priorities and address the legitimate demands of BSNL employees.

संपादकीय

वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण की त्रासदी

बीएसएनएल में डीओटी से स्थानांतरित होकर समाहित दूरसंचार कर्मचारियों की वेतन पुनरीक्षण एवं समाहित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन पुनरीक्षण का मुद्दा आधार में लटका हुआ है। ज्ञातव्य है कि दोनों प्रकार के पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से लंबित है। प्रबंधन एवं सरकार इन दोनों मुद्दे को किसी भी स्तर पर इसकी अहमियत को नहीं समझते हुए हल्के रूप में ले रही है। अभी दिनांक 26 नवंबर 2024 को माननीय संचार मंत्री, भारत सरकार ने श्री एस. वेंकटेशन, माननीय सदस्य लोकसभा द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए यह बताया है कि बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन पुनरीक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नहीं हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने आगे यह लिखा है कि कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण बीएसएनएल के चल रहे आर्थिक संकट के कारण संभव नहीं है। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन पुनरीक्षण वेतन पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय संचार मंत्री ने उक्त पत्र में यह भी लिखा है कि पेंशन पुनरीक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में लंबित है परंतु यह सर्वविदित है कि माननीय प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने पेंशन कर्मचारियों के पक्ष में स्पष्ट निर्णय होने के बाद भारत सरकार के संचार मंत्रालय के निर्देश पर दूरसंचार विभाग में अपील दायर करके इस मामले को उलझाने की कोशिश की है। इससे स्पष्ट है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली से पेंशन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मामले को ले जाया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे उलझाए रखना का प्रयत्न कर रही है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारी सन् 2000 में निगम बनने के उपरांत निगम में कार्य करने के लिए अपना विकल्प दिए थे कि उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी तथा सरकारी कोष से उनका पेंशन भुगतान किया जाएगा, परंतु आज की स्थिति में सरकार अपने मंत्री परिषद के फैसले के उपरांत किए गए लिखित वादा से मुकर रही है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश की सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसने दशकों तक देश की दूरसंचार सेवाओं को जन–जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन और पेंशन पुनरीक्षण से जुड़े गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यह संकट केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर कर्मचारियों के मनोबल और संगठन की कार्यक्षमता पर भी पड़ रहा है।

बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का अंतिम पुनरीक्षण 2007 में हुआ था। तब से, निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय घाटे, और सरकारी उपेक्षा ने बीएसएनएल की स्थिति को कमजोर किया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन पुनरीक्षण का न होना उनके जीवन स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। वहीं, पेंशनभोगी भी लगातार मुद्रास्फीति के कारण अपनी पेंशन के अवमूल्यन से जूझ रहे हैं।

सरकार बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए कई बार आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सुधार को प्राथमिकता नहीं मिली। यह सरकारी उदासीनता का प्रतीक है और कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करता है।

उचित वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है।

बीएसएनएल को प्राइवेट कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल से प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। लेकिन बिना उचित वेतन और सुविधाओं के, प्रतिभाशाली कर्मचारियों का पलायन हो रहा है।

महँगाई के इस दौर में पेंशन का पुनरीक्षण न होना, पेंशनभोगियों के लिए एक गंभीर चुनौती है।

सरकार को जल्द से जल्द वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों में विश्वास बढ़े।

पेंशनभोगियों के लिए नियमित रूप से महँगाई भत्ता बढ़ाने और पेंशन पुनरीक्षण की नीति लागू करनी चाहिए।

बीएसएनएल को वित्तीय संकट से उबारने के लिए नई तकनीकों और सेवाओं में निवेश करना आवश्यक है, जिससे कंपनी अपने राजस्व में सुधार कर सके।

सरकार को बीएसएनएल के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी चाहिए जो इसे निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाए।बीएसएनएल के वेतन और पेंशन पुनरीक्षण का मुद्दा न केवल आर्थिक सुधार की माँग करता है, बल्कि यह सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास बहाल करने का भी अवसर है।यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो यह न केवल कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण संस्था के भविष्य को भी खतरे में डाल देगा। अब समय आ गया है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएँ पुनः निर्धारित करे और बीएसएनएल कर्मचारियों की न्यायसंगत माँगों को पूरा करे।